



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18]
No. 18]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 4, 1974 (वैशाख 14, 1896)
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 4, 1974 (Vaisakhi 14, 1896)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग III—खण्ड 4

PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements
and Notices issued by Statutory Bodies

भारतीय जीवन बीमा निगम

भारतीय जीवन बीमा (निगम कर्मचारी-वर्ग) के विनियम, 1960
में संशोधन

सं० एड०/III(IIV)/51/74—जीवन बीमा निगम अधि-
नियम, 1956 की धारा 49 की उप-धारा (2) के खण्डों
(ख) और (खख) के अंतर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते
हुए और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदित के माध्यम भारतीय जीवन
बीमा निगम (कर्मचारी-वर्ग) के विनियम 1960 में, भारतीय
जीवन बीमा निगम निम्नलिखित संशोधन करता है।

अनुसूची II

(क) मद क : वेतन-मान के अंतर्गत प्रभाग III से सर्वाधिक
क्लास III (लिपिक और पर्यवेक्षी कर्मचारी-वर्ग) तथा प्रभाग IV
में सर्वाधिक क्लास IV (अधीन कर्मचारी-वर्ग) वेतन-मान के स्थान
पर निम्नलिखित वेतन-मान रखे जाएंगे, जैसे—

III क्लास III (लिपिक और पर्यवेक्षी वर्ग)

1. अधीक्षक रु० 370-25-470-
30-830

2. उच्च श्रेणी सहायक रु० 265-20-385-
रु० 25-735

टिप्पणी आंतरिक लेखा-परीक्षा सहायक जो उच्च श्रेणी
सहायक के वेतन-मान में हो उन्हें रु० 40 का विशेष
वेतन प्रति मास पहले 5 वर्षों की सेवा के लिए

मिलेगा तदनुसार रु० 45 प्रतिमास अगले 5
वर्षों की सेवा के लिए मिलेगा तदनुसार. रु० 50
प्रतिमास 10 वर्ष की सेवा के पश्चात् मिलेगा।

3 अनुभाग प्रमुख रु० 225-15-255-
20-395-25-670

टिप्पणी सहायक जिनकी पदोन्नति 1 अप्रैल, 1973
को या उसके बाद अनुभाग प्रमुख के वर्ग में हुई
हो वे चाहे तो सहायकों को ही वेतन-मान (जो इसी
में आगे क्रम संख्या 5 के सामने दिया गया है)
लेकर कार्य करते रह सकेंगे और नीचे दिया हुआ
निर्धारित विशेष वेतन पाएंगे या फिर अनुभाग
प्रमुखों के उपरोक्त वेतन-मान में फिर किये
जाएंगे। यह पर्याय, पदोन्नति के पश्चात् तीस
दिन के अन्दर प्रयोग में लाना होगा और एक बार
बुना हुआ पर्याय अंतिम माना जाएगा।

रु० 40 प्रति मास पहले 5 वर्षों की सेवा के लिए
तदनुसार।

रु० 45 प्रति मास अगले 5 वर्षों की सेवा के लिए
तदनुसार।

रु० 55 प्रतिमास अगले 5 वर्षों की सेवा के लिए
तदनुसार।

4. आशुलिपिक रु० 210-15-225-20-
405-25-430-कु० रो०-
25-630 ।

टिप्पणी : आशुलिपिक ग्रेड के आशुलिपिकों को निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारियों के साथ काम करने के लिए चुना हो तो उन्हें निम्नलिखित विशेष वेतन मिलेगा :

- अध्यक्ष रु० 65 प्रतिमास
निदेशक क्षेत्रीय प्रबंधक रु० 55 प्रतिमास
उप क्षेत्रीय-प्रबंधक और
समान श्रेणी के अधि-
कारी 40 प्रतिमास

विभागीय प्रबंधक रु० 30 प्रतिमास
आशुलिपिक ग्रेड के आशुलिपिक जो उपर्युक्त अधि-
कारियों के साथ संलग्न न हों उन्हें रु० 20 प्रति-
मास विशेष वेतन मिलेगा ।

5. सहायक रु० 175-10-215-15-
290-20-410-कु० रो०-
25-585 ।

6. लेन-देन रोकड़ियां कैशियर इनका वेतन-मान सहायकों
के वेतन-मान जैसा होगा
और उन्हें रु० 25 प्रतिमास
विशेष वेतन अधिक मिलेगा

- | | | |
|--|---|--|
| 7. टंकक | } | इनका वेतन-मान सहायक के
वेतन-मान जैसा है,
उन्हें रु० 25 प्रतिमास
कार्य-भत्ता अधिक मिलेगा |
| 8. टेलिफोन आपरेटर | | |
| 9. एड्रसिंग मशीन एवं पंच
कार्ड आपरेटर | | |
| 10. काम्पटोमीटर आपरेटर | | |
| 11. भत्ता पानेवाला प्रक्षेपक | | |

टिप्पणी : (1) स्नातक, जो 4 से 11 तक के वर्गों में नियुक्त किये गये हों उन्हें 2 वेतन-वृद्धियां स्थायीकरण पर दी जाएंगी ।

- (2) 4 से 11 तक के वर्गों के स्थायी कर्मचारी से दो वेतन-वृद्धियां उस माह जो उस माह के आगे आता हो के पहले दिन से दी जाएगी, जिसमें कि यह घोषित किया गया था कि उसने प्रथम डिग्री परीक्षा पास कर ली है ।

- 12 अभिलेख लिपिक रु० 150-6-162-8-218-
10-238-कु० रो०-10-
258-12-270-15-390

टिप्पणी : बांदा और अनुलिपित प्रचारक जो इस वेतन-मान में काम करते हों उन्हें रु० 15 प्रतिमास कार्य-भत्ता मिलेगा ।

IV क्लास IV (अधीन कर्मचारी वर्ग) .

1. भाडूकश और क्लीनर रु० 120-5-160-6-
196-7-224-8-240 ।

2. चपरासी हमाल, मुख्य चप-
रासी, लिफ्टमैन, चौकीदार,
दफ्तरी रु० 125-5-165-6-
201-7-229-8-245 ।

3. मोटर-चालक रु० 166-5-181-6-
199-7-234-8-274-
9-310 ।

टिप्पणी : (i) मुख्य चपरासी, लिफ्टमैन और चौकीदारों को रु० 10 प्रतिमास विशेष वेतन मिलेगा ।

- (ii) जो चपरासी ड्यूटी के अधिकतर समय में कैबिंग मशीन पर काम करते हों उन्हें रु० 10 प्रतिमास कार्य-भत्ता मिलेगा ।

(ख) प्रभाग IV के बाद निम्नलिखित प्रभाग IV-क जोड़ दिया जाएगा —

"IV-क वेतन-मान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के बाद मूल-वेतन में बढ़ोतरी —

- (1) क्लास III (लिपिक तथा पर्यवेक्षी) या क्लास IV (अधीन) कर्मचारी-वर्ग के किसी कर्मचारी को जो अपने वेतन-मान के अधिकतर स्तर तक पहुंच चुका है, उसके कार्य का रिकार्ड संतोषप्रद पाये जाने पर, अधिकतम स्तर तक पहुंचने के बाद की गई सेवा के प्रत्येक दो वर्ष के लिए उसके मूल वेतन में अनिवार्य बढ़ोतरी प्रदान की जाएगी जो उसके वेतन-मान की आखिरी वृद्धि के बराबर होगी ।

व्यवस्था है कि यदि एक कर्मचारी को वह बढ़ोतरी आखिरी वृद्धि या बढ़ोतरी (जो भी हो) की तारीख से दो वर्ष की सेवा के अंत में प्रदान न की गई हो तो उसका मामला प्रत्येक पंचांग वर्ष के उस माह से अगले माह में पुनरीक्षण-योग्य होगा, जिसमें वह बारह माह की सेवा पूरी करता हो और तब तक बढ़ोतरी प्रदान न की गई हो और यदि बढ़ोतरी प्रदान करना तय किया जा चुका हो तो यह बढ़ोतरी जिस पंचांग वर्ष में बढ़ोतरी करने का निर्णय किया गया हो, उसके जिस माह से पुनरीक्षण-योग्य हुआ हो, उस माह की पहली तारीख से लागू होगी ।

आगे व्यवस्था है कि किसी भी कर्मचारी का ऐसी तीन बढोतरी से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) उप-खण्ड (1) में उल्लिखित बढोतरी प्रदान करने के आगे में मक्षम अधिकारी यह होगा जो इस कर्मचारी को कजलता रोध पार करने की अनुमति देने के लिए मक्षम है।

(ग) मद ख महंगाई-भत्ता, के अंतर्गत खण्ड (iii) में उप-शोर्षक "दर" के सामने दिये गये ग्रंथ के तीसरे शब्द में "भारतीय अमित परिवर्तन" के पार "य भारत का राजपद, जो भी प्रकाशना शास्त्र उपलब्ध हो" शब्द और विगत चिह्न आड़ दिये जाएंगे।

(घ) मद घ. पर भाषा गता क अंतर्गत खण्ड (iii) के प्रावधान क्लास III लिपिक तथा पर्यवेक्षी) कर्मचारी-वर्ग और क्लास IV (अधीन) कर्मचारी-वर्ग के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान रखा जाएगा जैसे—

‘घरभाड़ा भत्ता मूल वेतन (विशेष वेतन सहित) के 10 की दर से दिया जाएगा जो क्लास III कर्मचारियों के आगे में कम से कम रु० 28 प्रतिमास और क्लास IV कर्मचारियों के बारे में कम से कम रु० 22 प्रतिमास और किसी भी मामले में अधिक से अधिक रु० 40 होगा।’

ड) मद ड नगर प्रतिपुरा भत्ता के अंतर्गत—

(i) मद (ii) के अंतर्गत विद्यमान प्रविष्टि उसके खण्ड (क) वत् दिखाई जाएगी और उसमें से “क्लास III (लिपिक तथा पर्यवेक्षी) और क्लास IV (अधीन) कर्मचारी-वर्ग शब्द निकाल दिये जाएंगे तथा

(ii) निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाएगा, जैसे—
(ख) क्लास III (लिपिक तथा पर्यवेक्षी) और क्लास IV (अधीन) कर्मचारी-वर्ग, जो उपरोक्त फेन्टो पर रहत है वे रु० 20 प्रतिमास नगर पूरक-भत्ता पाएंगे।

2 कथित विनियमों के 76 वे विनियम में, उप-विनियम (1) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम (1क) वत् समाविष्ट होगा, जैसे—

“(1क) जहां एक कर्मचारी पक्षास III या क्लास IV का कर्मचारी हो तो उप-विनियम (1) के प्रावधान 1 अप्रैल, 1973 से ऐसे लागू होंगे जैसे कि उसमें आये ग्रंथ “8” के स्थान पर ग्रंथ “10” रख दिया गया हो।”

3 कथित विनियमों के 77 वे विनियम में उप-विनियम (3) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम (3क) वत् जोड़ दिया जाएगा, जैसे—

“(3क) जहां एक कर्मचारी क्लास III या क्लास IV का कर्मचारी हो तो उसके बारे में देय आनुतोषिक वह होगा जो

पूर्वगामी उप-विनियमों के अनुसार निश्चित करने पर या (यहां इसमें दिये गये परन्तुष की शर्त पर) आनुतोषिक भुगतान अधिनियम, 1972-जैसा कि यह 24 जनवरी, 1974 को लागू था (जो अब से उक्त अधिनियम वत् उल्लिखित होगा) के अंतर्गत परिकल्पित करने पर जो भी कर्मचारी के अधिक हित में हो वह लागू होगा।

व्यवस्था है कि—

(क) उक्त अधिनियम के अंतर्गत आनुतोषिक के परिकल्पन के लिए, कर्मचारी का मासिक वेतन, उसका अंतिम मूल-वेतन (विशेष वेतन मिलाकर), महंगाई भत्ता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता ही माना जाएगा।

(ख) उक्त अधिनियम के प्रावधान, उसका ऊपर उल्लिखित मासिक वेतन रु० 1000 से अधिक हो, तो भी लागू किये जाएंगे।

(ग) ऐसे कर्मचारी के मामले में, जिसकी मृत्यु निगम की सेवा में रहते हुए 15 वर्षों की निरन्तर सेवा पूरी करने पर हो जाए तो उक्त अधिनियम के अंतर्गत आनुतोषिक, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के एक मास के वेतन की दर से परिकल्पित किया जाएगा और अन्य सभी मामलों में उसी दर से गिना जाएगा जो उक्त अधिनियम में निश्चित की गई है, और

(घ) जहां उक्त अधिनियम के अंतर्गत यहाँ निश्चित किये गये ढग से परिकल्पित आनुतोषिक केवल रु० 20,000 से अधिक हो तो देय आनुतोषिक केवल रु० 20,000 ही माना जाएगा।

र० म० मेहता,
प्रबंधक निदेशक

मद्रास के रेल दर अधिकरण के समक्ष

(रेल दर अधिकरण नियमावली 1959 के नियम 19(3) और (4) के अधीन जारी की गयी सार्वजनिक सूचना)

1974 की शिकायत सं० 1

मैसर्स ग्वालियर रेयान सिल्क मैनुफैक्चरिंग (बीविंग) कं० लि० (पल्प इंडिजीन) बिरलाकूटम, मावुर कोपिक्कोड जिला, केरल राज्य जिमका प्रतिनिधित्व उक्त कंपनी के वित्त व वाणिज्य प्रबंधक श्री जे० सी० गोयल द्वारा किया जाता है

बताम

महा प्रबन्धक, दक्षिण रेलवे प्रशासन, मद्रास प्रत्यर्थी

शिकायतकर्ता भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा 41(1) (क), (ख) और (ग) के अधीन पेश की गयी अपनी शिकायत में यह बताते हैं कि उनके अपने पल्प कारखाने में रेयान ग्रेड पल्प तैयार करने के लिए जलाने की लकड़ी कच्ची सामग्री होती है और वह रासायनिक प्रक्रिया के अधीन अत्यधिक ताप में जलायी जाती है; यह कि प्रत्यर्थी, जो भाड़ा-प्रभार वसूल करने के उद्देश्य से उसे “जलाने की लकड़ी” के अधीन वर्गीकृत करता

था, 1-4-70 से उसे "अन्यथा न वर्गीकृत-इमारती लकड़ी" के अधीन वर्गीकृत करने लगा, यह कि शिकायतकर्ता के ठेकेदारों द्वारा या तो कोषिकोड या वेस्ट हिल या गुलातूर रेलवे स्टेशनों में सप्लाई की जानेवाली उसी प्रकार की लकड़ी को 'जलाने की लकड़ी' के रूप में वर्गीकृत करके प्रत्यर्थी द्वारा शिकायतकर्ता के विरुद्ध खुले तौर भेद किया जाता है; यह कि "अन्यथा न वर्गीकृत-इमारती लकड़ी" का वर्गीकरण मनमाना और विभेदकारी है; यह कि इस प्रकार शिकायतकर्ता के लिए, उल्लाल, मगलूर, मेट्टटुप्पालयम, कारमडै, कोन्लम, पुनलूर, तिरुवनन्तपुरम, तिल्लूूर, अंगमाली और उदकमंडलम स्टेशनों में वेस्ट हिल, गुलातूर और कोषिकोड स्टेशनों को परिव्याहित होनेवाली जलाने की लकड़ी पर लगायी जाने वाली भाड़ा-दर अनुचित है।

शिकायतकर्ता ने प्रार्थना की है कि ऊपर निर्दिष्ट स्टेशन-युगलों के बीच रेलों द्वारा परिव्याहित होकर शिकायतकर्ता के कारखाने में उपयुक्त होने के लिए अभिप्रेत जलाने की लकड़ी को "अन्यथा न वर्गीकृत- इमारती लकड़ी" के रूप में वर्गीकृत करना अनुचित घोषित किया जाय और वैसे सामग्रियों के परि-

वहन के लिए उचित दर निर्धारित की जाय तथा परिणामी अनुतोष प्रदान किये जाएं।

अन- यह सार्वजनिक सूचना दी जाती है ताकि जिन व्यक्तियों का उपयुक्त शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी के जैसे इन कार्य-वाहियों में समान हित हो और जो व्यक्ति अधिकरण के समक्ष आवेदन पेश करना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अन्दर इस शिकायत में प्राथित अनुतोष की पुष्टि में या विरोध में प्रविष्ट होने की अनुमति के लिए या शिकायतकर्ता अथवा प्रत्यर्थी के पक्ष में जाड़ जाने के लिए आधार स्पष्ट करते हुए अधिकरण को आवेदन पेश करें। अधिकरण द्वारा इस सूचना के बाद जो भी फैसला सुनाया जायगा वह वैसे सभी लोगों पर लागू होगा।

आज 1974 के अप्रैल, की बाईसवी तारीख को नं० 11, बोट क्लब रोड, राजा ग्रणामलैपुरम, मद्रास-600028 में मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुहर के अधीन दिया जाता है।

एन० बी० मुन्नामणियम सचिव

BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL, MADRAS

(Public Notice under Rule 19(3) and (4) of the Railway Rates Tribunal Rules 1959).

Complaint No. 1 of 1974.

Messrs. Gwalior Rayon Silk Mfg. (Wvg) Co. Ltd., (Pulp Division) Birlakootam, Mavoor, Kozhikode District, Kerala State, represented by Shri J. C. Goyal, Finance and Commerce Manager of the Company.—Complainant

Versus

The General Manager, Southern Railway Administration, Madras.—Respondent

The Complainant in a complaint filed under Sec. 41(1) (a) to (c) of the Indian Railways Act 1890, States that firewood is a raw material for the manufacture of rayon grade pulp in their pulp plant and in the chemical process it is burnt at a high temperature; that the respondent who used to classify the material as 'firewood' for the purpose of freight collection began to classify it from 1-4-70 as Timber N.O.C.; that an open discrimination is shown to the complainant by the respondent by classifying the same type of wood consigned by the complainant's contractors to be delivered either at Calicut or at West Hill or at Elathur railway stations as 'firewood'; that the classification of firewood as "Timber N.O.C." is arbitrary and discriminatory; that the rate for the carriage of firewood for the complainant from the stations, Ullal, Mangalore, Mettupalayam, Karamadai, Quilon, Punalur, Trivandrum, Nilambur, Angamaly and Ootacamund to the stations West Hill, Elathur and Calicut is thus unreasonable.

The complainant has prayed for a declaration that classification firewood intended to be used for the complainant's plant, transported by rail between the above specified pairs of stations as "Timber N.O.C." is unreasonable and to fix a reasonable rate for the carriage of the same and for consequential reliefs.

This public notice is, therefore, given so that persons having the same interest in the proceedings as the Complainant or the respondent above named and who desire to petition the Tribunal may do so within thirty days of the publication of this notice setting forth the grounds for leave to intervene, in support of or in opposition to the reliefs sought for in the complaint or be added as a party on the side of the complainant or the respondent. Any decision given by the Tribunal after the public notice shall apply to all such persons.

Given under my hand and seal of the Tribunal, this 22nd day of April 1974, at No. 11 Boat Club Road, Jajah Annamali-puram, Madras-28

N. V. SUBRAMANIAN
Secretary

'Seal of Tribunal'

THE FOOD CORPORATION OF INDIA

HEAD OFFICE

New Delhi, the 25th April 1974

No 1-12/73-EP.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:—

- (1) These Regulations may be called the Food Corporation of India (Staff) (19th Amendment) Regulations, 1974.
- (2) These shall be deemed to have come into force on the 21st Dec., 1973.

2. The post of Manager (Legal) has been upgraded from the existing scale of Rs. 1600-100-2000 to Rs. 2000-100-2500 re-designated as Chief Legal Manager till further orders.

Accordingly, the following insertion should be made as S. No. 7(A) in part I—special posts of Appendix—I of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 :—

(i) Recruitment Rules for the post of Chief Legal Manager as shown in the attached statement should be incorporated as Serial No. 7(A).

PART-I SPECIAL POSTS

THE FOOD CORPORATION OF INDIA

Sl No	Description of post	Scale of pay Rs.	Mode of recruitment	Promotion		Direct recruitment		Corresponding categories of posts in Directorate General of Food	Remarks
				Selection/non-selection	Experience	Qualification and experience if any	Age limit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7(A)	Chief Legal Manager	2000-100-2500	**	—	—	(i) Degree in Law from a recognised University. (ii) At least 15 year experience as Legal Officer in Central/State Government or Public/Private Sector undertaking or 10 years practice at the Bar.	45 years	—	**Mode of recruitment to be decided at the time of appointment.

B. D. BERERA
Senior Deputy Manager (EP)

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Amendments to the Life Insurance Corporation of India

(Staff) Regulations, 1960

In exercise of the powers vested in it under clauses (b) and (bb) of Sub-Section 2 of Section 49 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 and with the previous approval of the Central Government, the Life Insurance Corporation of India makes the following amendments to the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations, 1960.

SCHEDULE II

(a) Under Item A, SCALES OF PAY, for the scales of pay set forth in Division III in respect of Class III (Clerical and Supervisory Staff) and Division IV in respect of Class IV in (Subordinate Staff) the following scales of pay shall be substituted, namely :—

III. Class III (Clerical and Supervisory Staff) :—

1. Superintendents—Rs. 370-25-470-30-830
2. Higher Grade Assistants—Rs. 265-20-385-EB-25-735

NOTE : Internal Audit Assistants who are in Higher Grade Assistant's scale will receive a special pay of Rs. 40/- per month for the first 5 years of service as such, Rs. 45/- per month for the next five years of service as such, Rs. 50/- per month after 10 years of service as such.

3. Section Heads—Rs. 225-15-255-20-395-25-670.

NOTE : Assistants who are promoted to the Section Head's cadre on or after 1st April, 1973 shall have the option to continue in the scale of pay of Assistants set forth against serial No. 5 herein and draw the appropriate Special Pay specified below or to be fitted in the above scale of Section Heads. Such option shall be exercised within thirty days from the date of promotion and the option once exercised shall be final.

- Rs. 40/- per month in the first five years of service as such;
- Rs. 45/- per month in the next five years of service as such;
- Rs. 55/- per month in the next five years of service as such;
4. Stenographers—Rs. 210-15-225-20-405-25-430-EB-25-630.

NOTE : Stenographers in the Stenographer's grade selected to work with the officers of the following rank will receive a special pay on the following scale :—

Chairman :—Rs. 65/ per month

Director/Zonal Manager :—Rs. 55/- per month

Dy. Zonal Managers &

Officers of equivalent rank :—Rs. 40/- per month

Divisional Managers :Rs. 30/- per month

Stenographers in the Stenographer's scale who are not attached to the officers of the above ranks will receive a special pay of Rs. 20/- per month.

5. Assistants—Rs. 175-10-215-15-290-20-410-EB-25-585

6. Receiving & Paying Cashiers—Same as Assistants scale with a special pay of Rs. 25/- per month.

7. Typists—Same as Assistant's scale with a functional allowance of Rs. 25/- per month.

8. Telephone Operators—Same as Assistant's scale with a functional allowance of Rs. 25/- per month.

9. Addressing Machine & Punch Card Operators—Same as Assistant's scale with a functional allowance of Rs. 25/- per month

10. Comptometer Operators—Same as Assistant's scale with a functional allowance of Rs. 25/- per month.

11. Projectionists receiving an allowance—Same as Assistant's scale with a functional allowance of Rs. 25/- per month.

NOTE : (1) Graduates appointed to categories 4 to 11 will receive two increments on confirmation.

(2) A permanent employee in categories 4 to 11 will receive two increments with effect from the first day of the month following that in which it is declared that he has passed the first degree examination.

12. Record Clerks—Rs. 150-6-162-8-218-10-238-EB-10-258-12-270-15-390.

NOTE : Banda & Duplicating Machine Operators who are in this scale, will receive a functional allowance of Rs. 15/- per month

IV. Class IV (Subordinate Staff) :

1. Sweepers & Cleaners—Rs. 120-5-160-6-196-7-224-8-240.

2. Sepoys, Hamals, Head Peons, Liftmen & Watchmen, Daftries—Rs. 125-5-165-6-201-7-229-8-245.

3. Drivers—Rs. 166-5-181-6-199-7-234-8-274-9-310.

NOTE : (i) Head Peons, Liftmen and Watchmen will receive a special pay of Rs. 10/- per month.

(ii) Sepoys operating franking machines as a major part of their duties will receive a functional allowance of Rs. 10/- per month

(b) After Division IV, the following shall be added as Division IV-A, namely :—

IV-A ADDITION TO BASIC PAY AFTER REACHING THE MAXIMUM OF THE SCALE :

(1) An employee in Class III (Clerical and Supervisory) or Class IV (Subordinate) Staff who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him may, subject to the record of his work being found satisfactory, be granted for every two years of service put in by him after reaching such maximum an addition to his basic pay, which shall be equal to the last increment drawn by him in the scale :

Provided that where an employee is not granted such addition at the end of two years of service from the date of last increment or addition, as the case may be, his case shall fall due for review in each calendar year in the month following that in which he completes twelve months of service in that year, so long as he has not been allowed the addition; and if it is decided to allow the addition, it shall take effect from the first of the month in which the review has fallen due in the calendar year in which the decision is taken to allow the addition.

Provided further that no employee shall be allowed more than three such additions.

(2) The competent authority to grant the addition referred in sub-clause (1) shall be the authority competent to allow the employee to cross efficiency Bar."

(c) Under Item B. DEARNESS ALLOWANCE, in clause (iii) in the third sentence appearing against the sub-heading "Rate", after the words "Indian Labour Journal", the words and punctuation "or the Gazette of India, whichever publication is available earlier" will be inserted.

(d) Under Item D. HOUSE RENT ALLOWANCE for the provision in clause (iii) Class III (Clerical & Supervisory) and Class IV (Subordinate) Staff, the following provision shall be substituted, namely :—

"The House Rent Allowance shall be at the rate of 10% of the basic pay (including special pay) with a minimum of Rs. 28 - per month in the case of Class III employees and with a minimum of Rs. 22/- per month in the case of Class IV employees, subject to a maximum of Rs. 40/- in either case"

(e) Under Item E. CITY COMPENSATORY ALLOWANCE—

(i) The existing entry under item (ii) shall appear as clause (a) thereof and the words "and Class III (Clerical & Supervisory) & Class IV (Subordinate) employees" therein shall be deleted; and

(ii) the following clause shall be added, namely :—

(b) Class III (Clerical & Supervisory) & Class IV (Subordinate) employees stationed at the above centres will receive City Compensatory Allowance of Rs. 20/- per month".

2. In Regulation 76 of the said Regulations, after sub-regulation (1) the following sub-regulation shall be inserted as sub-regulation (1A), namely—

"(1A) where an employee is an employee in Class III or Class IV, the provisions of sub-regulation (1) shall, with effect from 1st April, 1973, apply as if for the figure "8 1/3" appearing therein, the figure "10" had substituted."

3. In Regulation 77 of the said Regulations, after sub-regulation (3) the following sub-regulation shall be added as sub-regulation (3A) :—

"(3A) where an employee is an employee in Class III or Class IV, gratuity admissible in his case shall be determined in accordance with the provisions of the foregoing sub-regulations or calculated (subject to the terms of the proviso herein) under the Payment of Gratuity Act, 1972, as it stood on 24th January, 1974 (hereinafter referred to as the said Act), whichever is more favourable to him :

Provided that—

(a) While calculating the gratuity under the said Act the monthly salary of an employee shall be deemed to be his terminal basic pay (including special pay), Dearness Allowance and additional Dearness Allowance;

(b) the provisions of the said Act shall be applied notwithstanding that his monthly salary as above is over Rs. 1000/-;

(c) in the case of an employee who dies while in the service of the Corporation after having completed 15 years of continuous service, the gratuity under the said Act shall be calculated at the rate of one month's salary for every completed year of service, and in all other cases at the same rate as specified in the said Act; and

(d) where the gratuity calculated under the said Act in the manner specified herein exceeds Rs. 20,000/-, the gratuity payable shall be deemed to be Rs. 20,000/- only.

R. M. MEHTA
Managing Director

THE BAR COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT OF RULES

At its meeting dated 24th March, 1974, the rules of the Bar Council of India have been amended as set out in the following resolutions :—

1. Rules in Part III, Chapter II

Resolution No. 19/1974.—A.—RESOLVED that the Rules of the Council in Part III, Chapter II, be and are hereby amended as follows with effect from 24th March, 1974 :—

I. In lieu of the existing provision in the Proviso (i) to Rule 3(a), substitute the following :—

(i) No candidate whose name has not been on the State Roll for at least 10 years shall be elected under Section 3(2) (b) and the proviso thereto of the Act—

(a) if 7 candidates of less than 10 years standing in the case of a State Council where 15 members are to be elected, have been declared elected or

(b) if 10 candidates of less than 10 years standing in the case of a State Council where 20 members are to be elected, have been declared elected or

(c) if 12 candidates of less than 10 years standing in the case of a State Council where 25 members are to be elected, have been declared elected.

II. In provisos (ii) and (iv) of the existing rule 3(a) in lieu of the words "proviso to Section 3(2)" substitute the words "proviso to Section 3(2)(b)".

III. In Rule 3(b)(1)(ii) for the paragraph beginning with the words "First such candidates" and ending with the words "Other Bar Councils" substitute the following :—

"First such candidates whose names are on the State Roll for less than 10 years, if the number of such candidates declared elected as provided for in these rules is :—

(a) 7 in the case of a State Council where in all 15 members have to be elected; or

(b) 10 in the case of a State Council where in all 20 members have to be elected; or

(c) 12 in the case of a State Council where in all 25 members have to be elected."

IV. In lieu of the existing illustration in rule 3(b)(1)(ii) of the rules, substitute the following :—

Illustration No. 1.—At an election to a State Council where under the Act and these rules, the total number of elected members is 20, 300 is arrived at as the quota. At the end of a count, when there is no further surplus to be distributed, M and N are the contesting candidates.

M whose name has not been on the State rolls for at least 10 years gets 150, and

N whose name has not been on the State rolls for at least 10 years gets 100.

Only 9 candidates whose names have been on a State Roll for at least 10 years have already been declared elected. Hence M has to be excluded and the voting papers of M will be thereafter transferred as provided for in these rules.

If in the same case, 10 candidates whose names have been on a State roll for not less than 10 years had already been declared elected, N will be excluded. The voting papers of N will be transferred as provided in these rules.

Illustration No. 2.—At an election to a State Council where under the Act and these rules, the total number of elected members is 15, 300 is arrived at as the quota. At the end of

a count, when there is no further surplus to be distributed. M and N are the contesting candidates.

M whose name has not been on the State rolls for at least 10 years gets 150; and

N whose name has been on the State rolls for more than 10 years gets 100.

Only 7 candidates whose name have been on a State roll for at least 10 years have already been declared elected. Hence M has to be excluded and the voting papers of M will be thereafter transferred as provided in these rules.

If in the same case, 8 candidates whose names have been on a State roll for not less than 10 years had already been declared elected, N will be excluded. The voting papers of N will be transferred as provided for in these rules.

Illustration No. 3.—At an election to a State Council where under the Act and these rules the total number of elected members is 25, 300 is arrived at as the quota. At the end of a count, when there is no further surplus to be distributed, M and N are the contesting candidates.

M whose name has not been on the State rolls for at least 10 years gets 150, and

N whose name has been on the State rolls for more than 10 years gets 100

Only 12 candidates whose names have been on a State roll for at least 10 years have already been declared elected. Hence M has to be excluded and the voting papers of M will be thereafter transferred as provided in these rules.

If in the same case, 13 candidates whose names have been on a State roll for not less than 10 years had already been declared elected, N will be excluded. The voting papers of N will be transferred as provided for in these rules.

V. In lieu of the words in Rule 3(c)(i) beginning with the words "If the total number of" and ending with the words "be declared elected" substitute the following :—

"If the total number of candidates so far declared elected from amongst the advocates whose names have been on the State roll for at least 10 years at the relevant date, is less than—

- (i) 8 in the case of a State Council where 15 members are to be elected, or
- (ii) 10 in the case of a State Council where 20 members are to be elected, or
- (iii) 13 in the case of the State Council where 25 members are to be elected

then, the requisite number of candidates of such standing shall first be declared elected and only the balance from amongst other candidates shall be declared elected"

II. Amendments of Rules in Chapter V, Part II

Resolution No. 31/1974.—A.—RESOLVED that the Rules of the Council in Chapter V, Part II be and are hereby amended as follows :—

- (i) In lieu of Rule 7, substitute the following :—

"7. The Accountant shall draw a salary in the grade of Rs 520-20-700-25-950, with effect from 1-1-1973."

- (ii) In lieu of Rules 10, substitute the following :

"10. The Accountant and other permanent members or the staff shall be entitled to Dearness Allowance, House Rent Allowance and City Compensatory Allowance from 1-1-1973 at the rate as is paid to the staff of the Supreme Court of India."

III. Rules in Part III-A

Resolution No. 20/1974.—RESOLVED that Rules 1 and 10 of the Rules of the Council in Part III-A be and are hereby amended as follows with effect from 24th March, 1974 :—

I. That in lieu of Rule 1 of the existing Rules the following be substituted :—

- "1. (1) Save as provided in Section 24(1)(c) (iia) of the Act, a degree in law obtained from any university in the territory of India after the 12th March, 1967 shall not be recognised for purposes of Section 24(1)(c)(iii) of the Act unless the following conditions are fulfilled :—

- (a) That at the time of joining the course of instruction in law for a degree in law, he is a graduate of University, or possesses such academic qualifications which are considered equivalent to a graduate's degree of a University by the Bar Council of India,
- (b) that the law degree has been obtained after undergoing a course of study in law for a minimum period of three years as provided in these rules, and
- (c) that the course of study in law has been by regular attendance at the requisite number of lectures, tutorials and moot Courts in a college recognised by a University.
- (2) (a) The Council shall publish a notification in the Gazette of India and the prominent newspapers in India, names of Universities whose degrees are recognised under the rules in this Chapter: and
- (b) send a copy of the notification above referred to to all the Universities
- (3) Information about the non-recognition or derecognition of the degree in law of any University may also be sent to Universities in India and the State Bar Councils.

II. That the existing Rule 10 be deleted.

New Delhi 16th April 1974 A. N. VEFRARAGHAVAN
Secretary
Bar Council of India

OFFICE OF THE PUNJAB WAKF BOARD, AMBALA CANTONMENT

In exercise of the powers conferred u/s 22 of the Wakf Act 1954 the Punjab Wakf Board delegates the following powers to the Chairman in supersession of all previous delegations vide resolution no. 2 dated 19-4-1974 in the meeting held at 9.00 AM

- 1 To supervise and control the administration of the Wakf Board generally in all matters
2. To advise and direct the Secretary in the proper performance of the duties and exercise of powers conferred on him.
- 3 To sanction T.A. and other allowances to the Secretary, members of the Board and members of the Committees.
4. To sue and defend cases on behalf of the Board in Civil, Criminal and Revenue Courts and other offices and engaging advocates for the same and take all legal and proper steps concerning Wakf properties, to sign papers on behalf of the Wakf Board, sanction the prescribed court fee and expenses and to sanction legal fees upto Rs. 1100/- in each case.
- 5 To institute and defend all appeals, revisions, review and execution applications in any court, office or before any authority.
- 6 To exercise the powers and performance of duties of the Board under the Act in emergent cases except in regard to the matters in which the Act prescribes the consent of a specific majority of the members of the Board. The Chairman should report the action taken by him in this behalf to the Board at its next meeting.

7. Such other powers and duties as have been conferred or imposed on the Chairman by the Act or under the Rules and Regulations framed thereunder.

In exercise of the powers conferred u/s 22 of the Wakf Act, 1954, the Punjab Wakf Board delegates the following powers to Smt. Sajida Begam, its member, vide resolution no 2/A dated 19-4-1974 held at 9-00 AM.

1. To sanction expenditure and make payments within the approved budget upto the extent of Rs. 1000/- on a single item and in emergent cases upto Rs. 2000/-
2. Sanction repairs of buildings upto Rs. 5000/- in each case and expenditure on Urs upto 1000/- in each case.
3. Write off of moveable property of value upto Rs. 500/-
- 4 Sanction upto 1000/- on repair of vehicle at a time
- 5 Sanction refunds upto Rs. 2000/-.
6. To order for auction and sanction sale where the value of the moveable property or article does not exceed Rs. 2000/-.

In exercise of the powers conferred under section 22 of the Wakf Act, 1954 the Punjab Wakf Board, Ambala Cantt delegates the following powers to its Secretary in supersession of all previous delegations vide resolution No. 2/B dated 19th April 1974 held at 9-00 A.M.

1. To examine the report of the Wakf Commissioner and publish in the official gazette the list of Wakfs with all the particulars prescribed in rule 4 of the Rules under the Act

2. To use and defend cases on behalf of the Board in Civil, Criminal and Revenue Courts, offices and before any authority engaging advocates for the same and take proper and legal steps concerning wakf properties. He shall sanction the prescribed court fees and be competent to sanction legal fees upto Rs 330/- in each case

3. To institute and defend appeals, revisions, review and execution applications in all courts or before any authority

4. To take measures for recovery of lost properties of any wakf.

5. To call for such return, statistics, accounts and other information from the Mutawallis in respect of wakf properties as found necessary or as the Board may from time to time require.

6. To inspect or cause inspection of wakf properties, accounts records or deeds and documents relating thereto

7. To allow inspection of the proceedings or other records of the Board and to issue copies of the same on payment of prescribed fees

8. To exercise the powers and to perform the functions of Board under section 25 in respect of the registration of wakfs in undisputed cases and in the maintenance of the register of wakfs under section 26.

9. To cause the registration of wakfs and to amend the register of wakfs under section 26

10. (a) To examine and provisionally approve the budget of Mutawallis whose income does not exceed Rs. 2000/- per annum in each case.

(b) To pass orders on audit reports under section 34 of the accounts of Wakfs whose income does not exceed Rs. 2000/- per annum

11. To convey the formal consent of the Board to any person or authority to institute a suit to obtain any of the reliefs referred to in section 55 of the Act.

12. To deposit and withdraw the amounts required to be deposited or withdrawn according to law in respect of suits instituted or defended by the Board.

13. To take necessary steps for the proper recording of wakf properties with the authorities concerned with the settlement and consolidation of Holdings operations by the State Government

14. Subject to the Regulations framed under section 68 of the Act to carry on day to day administration of the Board including :

(a) Drawing and disbursing of bills;

(b) Sanction of T.A. of staff;

(c) Make appointments and transfers of class III and those of class II with the approval of Chairman;

(d) Approve of Tour programme of officers, his own being approved by the Chairman;

(e) Make leave arrangements and grant leave

(f) Grant annual increments;

(g) Fix pay in already sanctioned scale;

(h) Sanction purchase of books, stationery and furniture subject to maximum of Rs. 200/- on one occasion.

(i) Sanction Rs. 500/- in each case on repairs or maintenance of buildings and Urs;

(j) Sanction of Rs. 300/- at a time on cost of petrol or insurance or registration charges or maintenance or vehicle.

(k) Sanction of Rs. 2000/- for printing and stationery at a time in case of survey provided that full powers will be exercised in payment of all the bills received from Government or Wakf Commissioner;

(l) Renew old scholarships which are in accordance with the instructions prescribed by the Board.

(m) Renew old monthly grants of widows and Madassas.

(n) Sanction payments of Govt. dues without limit.

(o) accept tenders in respect of sanctioned items to a value of Rs. 5000/-.

(p) issue work orders for works and repairs.

(q) sanction refund upto Rs. 500/-

15. To sanction expenditure within the approved budget upto Rs. 500/- in cases of non-recurring expenditure and Rs. 150/- in case of recurring expenditure.

16. To sanction expenditure on printing of forms and on contingencies within the approved budget subject to a limit of Rs. 150/- on a single item

17. To submit to the Board for its adoption the draft of annual administrative report after the approval of the Chairman not later than the month of June every year.

18. To get the account of Board as well as those of Wakfs under the direct supervision of the Board audited at the end of every financial year as laid down in Wakf Act and submit the audit report to the Board

19. To submit to the Board every month a progress report of the collections of wakf contributions, rents, properties etc., and the arrears thereof

20. To submit to the Board every month a progress report of the cases pending in the courts of Law.

21. To sanction leases of agricultural land for a term not exceeding three years upto rental of Rs. 1000/- per annum subject to the Punjab Agrarian Acts

22. To order for auction and sanction sale where the value of the movable property or article does not exceed Rs. 1000/-

23. To sanction lease of vacant plots and properties in Urban areas not exceeding three years upto a monthly rent of Rs. 50/-

24. Such other powers and duties as have been specifically conferred or imposed upon him by the Act or under regulations

Resolution No. 2/C. —In exercise of the powers conferred under section 22 of the Wakf Act, 1954, the Punjab Wakf Board, Ambala Cantt., delegates the following powers to the Chairman, and the Secretary with the prior permission in writing of the Chairman, vide its Resolution No. 2/C dated 19-4-1974 held at 9-00 A.M. in supersession of its previous resolution No. 11 dated 30-6-1970.

1. To institute and defend all Writ Petitions filed by or against the Punjab Wakf Board in the Supreme Court, Punjab & Haryana High Court, Delhi High Court and the High Court of Himachal Pradesh, on behalf of the Board.

2. To engage counsel/counsels to prosecute or defend all Writ Petitions by or against the Punjab Wakf Board.

Delegation of powers—Resolution No. 2/D dated 19-4-74 passed in the meeting held at 9.00 AM.

In exercise of powers conferred under section 22 of the Wakf Act, 1954, the Punjab Wakf Board, Ambala Cantt. delegates the following powers to its Chairman and the Secretary in supersession of its previous resolution no. 22 dated 30-6-70

1. To defend all cases filed by the employees and ex-employees of the Board against the Board in any Court or office or before any authority including the industrial tribunal and the labour court

2. To authorise Shri Mohan Lal Gupta, M.A., LL.B., Wakf Counsel to appear in all such cases and references on behalf of the Board, to make all applications, file written statements/ replies, advance arguments and pursue all such cases on all hearings before any court or office or authority etc. as Law Officer of the Board.

GHAZANFAR ALI KHAN

Secretary